

विद्युत मंत्रालय के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्द और वाक्यांश

S.No.	Words in English	Meaning in Hindi	Usages in English	Usages in Hindi
1.	Concurrent list	समवर्ती सूची	Electricity is in the concurrent list in the Constitution	संविधान में विद्युत समवर्ती सूची में है।
2.	Strengthening	सुदृढ़ करना	Govt. of India is strengthening power distribution system in the country.	भारत सरकार देश में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर रही है।
3.	Providing electricity	बिजली उपलब्ध कराना	Providing electricity to the consumers including farmers is the primary responsibility of the states.	किसानों सहित उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व है।
4.	Electricity sector	विद्युत क्षेत्र	The primary aim of the Electricity Act, 2003 was to boost the electricity sector in the country.	विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रमुख उद्देश्य देश में विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देना था।
5.	Launch	शुरू करना	Prime Minister launched the scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)	प्रधान मंत्री ने "प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना" (सौभाग्य) की शुरुआत की।
6.	Household electrification	घरों का विद्युतीकरण	The aim of Saubhagya is to achieve universal household electrification by providing last mile connectivity and electricity connections to all remaining un-electrified households in rural and urban areas.	सौभाग्य का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अन्तिम छोर की कनेक्टिविटी और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों का विद्युतीकरण करना है।

7.	Reliable	विश्वसनीय	To facilitate state utilities to ensure quality and reliable 24x7 power supply in the urban areas, Government approved the "Integrated Power Development Scheme" (IPDS) on 20.11.2014	शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की बिजली कम्पनियों की सहायता करने के लिए सरकार ने दिनांक 20.11.2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) मंजूर की।
8.	Outlay	परिव्यय	A total outlay of Rs. 32,612 crore which includes a budgetary support of Rs. 25,354 crore has been provided by the Government of India	भारत सरकार द्वारा 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित कुल 32,612 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।
9.	Inter-Ministerial Committee	अन्तर-मंत्रालयी समिति	The scheme is being monitored by an inter-ministerial committee and a state level committee.	इस योजना की निगरानी एक अन्तर मंत्रालयी समिति और एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।
10.	Capacity addition	क्षमता बढ़ाना	To meet the increasing demand of electricity, substantial capacity addition has been done in the recent years.	विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हाल के वर्षों में काफी क्षमता बढ़ाई गई है।
11.	Amendment	संशोधन	The Union Cabinet had approved the proposal for amendment in Electricity Act, 2003 on 10th December, 2014 as contained in the Electricity (Amendment) Bill 2014.	केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में उल्लिखित अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए प्रस्ताव को 10 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित कर दिया।
12.	Introduced	पुरःस्थापित	The Electricity (Amendment) Bill 2014 was introduced in the Lok Sabha on 19.12.2014.	विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।

13.	Stressed	संकटग्रस्त	Central and State generating companies act as an aggregator of such stressed power assets.	केंद्र और राज्य उत्पादक कम्पनियां इस प्रकार की संकटग्रस्त विद्युत परिसम्पत्तियों के समूहक के रूप में काम करती हैं।
14.	Charging infrastructure	चार्जिंग सुविधा	Charging infrastructure for e-vehicles has been set up at various points.	बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए विभिन्न स्थानों पर चार्ज करने की सुविधा स्थापित की गई है।
15.	Affordable cost	सस्ती लागत	The National Electricity Policy (NEP) has provision of adequate reliable power at affordable cost with access to all citizens.	राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) में सभी नागरिकों को सस्ती लागत पर पर्याप्त विश्वसनीय विद्युत पहुंचाने का प्रावधान है।
16.	Decisive	निर्णायक	Centre and the States have to play a decisive and positive role in the scheme.	केंद्र और राज्यों को इस योजना में निर्णायक और सकारात्मक भूमिका अदा करनी है।
17.	Monitoring system	निगरानी प्रणाली	The Ministry of Power has adopted a robust monitoring system for the capacity addition programme	क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए विद्युत मंत्रालय ने सुदृढ़ निगरानी प्रणाली अपनाई है।
18.	Plant Load Factor	संयंत्र भार कारक	The Plant Load Factor (PLF) of Thermal Power Stations (TPSSs) is an index of utilization of the installed capacity.	ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार कारक संस्थापित क्षमता के उपयोग का सूचक है।
19.	Ultra Mega Power Project	बहुत बड़ी विद्युत परियोजना	Government of India has launched Ultra Mega Power Projects through Ministry of Power.	भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के जरिए बहुत बड़ी विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की है।
20.	Transmission system	पारेषण प्रणाली	Transmission system plays an important role in the power delivery system by establishing the vital link between the generating stations and the distribution system.	पारेषण प्रणाली उत्पादन केंद्रों और वितरण प्रणाली के बीच एक अत्यावश्यक लिंक बनाकर विद्युत पहुंचाने की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

21.	Joint team	संयुक्त दल	The joint team of Central Electricity Authority and concerned Thermal Power Plant visited the proposed site of the plant.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित ताप विद्युत संयंत्र के संयुक्त दल ने संयंत्र के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया।
22.	Aspects	पहलुओं	So many aspects have to be considered before taking a decision to set up a power plant.	विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लेने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होता है।
23.	Centralization	केंद्रीयकरण	Centralization of powers is not in the interest of the organization.	शक्तियों का केंद्रीयकरण संगठन के हित में नहीं है।
24.	Delegated	प्रत्यायोजित	Secretary (Power) has delegated certain financial powers to the Joint Secretary (Administration)	सचिव (विद्युत) ने कुछ वित्तीय शक्तियां संयुक्त सचिव (प्रशासन) को प्रत्यायोजित की हैं।
25.	Earmarked	निश्चित करना	The government has earmarked sufficient fund for this scheme.	सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त निधि निश्चित की है।
26.	Eco-friendly	पर्यावरण अनुकूल	The project may be sanctioned for having eco-friendly design.	पर्यावरण अनुकूल डिजाइन होने के कारण इस परियोजना को मंजूर किया जा सकता है।
27.	Ecology	पारिस्थितिकी	The forest dwelling tribal people have been given forest rights keeping in view the ecology of the place.	वन में रहने वाले जनजातीय लोगों को उस स्थान की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर वन अधिकार दिए गए हैं।
28.	Economical	मितव्ययी	Under the economical measure, more than one official may be provided transport facility by the same vehicle.	मितव्ययी उपाय के तहत, एक से अधिक अधिकारियों को एक ही वाहन से यातायात की सुविधा मुहैया कराई जाए।
29.	Certification agency	प्रमाणीकरण एजेंसी	Bureau of Indian Standards is the certification agency for quality control.	भारतीय मानक ब्यूरो गुणवत्ता नियंत्रण की प्रमाणीकरण एजेंसी है।

30.	Electrification work	विद्युतीकरण कार्य	The Secretary (Power) has written a demi-official letter to the Chief Secretaries of all State Governments, regarding early completion of electrification work of all household in their states.	सचिव (विद्युत) ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को अपने राज्यों में सभी घरों का विद्युतीकरण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र लिखा है।
31.	Great achievement	बड़ी उपलब्धि	The electrification of all the household in the country is a great achievement for the Government.	देश में सभी घरों का विद्युतीकरण करना सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है।
32.	Healthy competition	स्वस्थ प्रतिस्पर्धा	For creating an environment of healthy competition amongst various power distribution utilities of the States, an award scheme was instituted by the Ministry of Power.	राज्यों की विभिन्न विद्युत वितरण यूटिलिटीयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा पुरस्कार योजना बनाई गई थी।
33.	Erstwhile	पूर्ववर्ती	Erstwhile R-APDRP has been subsumed in IPDS	पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है।
34.	Deployment	उपयोग	Special efforts for the development and deployment of Smart Grids in India started in this decade under the aegis of Ministry of Power, Govt. of India.	इस दशक में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में भारत में स्मार्ट ग्रिडों के विकास और उपयोग के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं।
35.	Statutory body	सांविधिक निकाय	Bureau of Energy Efficiency (BEE) was set up as a statutory body on 1st March 2002 at the central level to facilitate the implementation of the EC Act.	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 01 मार्च, 2002 को केंद्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।

36.	Fuel consumption standard	ईंधन खपत मानक	The Government of India, Ministry of Power issued average fuel consumption standards for cars on 23rd April 2015.	भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2015 को कारों के लिए औसत ईंधन खपत मानक जारी किए थे।
37.	Energy conservation	ऊर्जा संरक्षण	The National Energy Conservation Awards are presented to industries and other establishments every year by the Ministry of Power with the objective of promoting energy conservation among all sectors of economy.	अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं।
38.	Charging station	चार्जिंग स्टेशन	CEA has drafted amendments to regulations of Central Electricity Authority (CEA) regarding Grid Connectivity and Safety of supply for Charging stations .	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और आपूर्ति की सुरक्षा के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के संशोधनों का प्रारूप तैयार किया है।
39.	Green Energy	हरित ऊर्जा	Under Green Energy commitment to Govt. of India, NTPC has committed to develop 10,000 MW of Renewal Energy Projects by 2022.	भारत सरकार की हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के तहत एनटीपीसी ने 2022 तक 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की प्रतिबद्धता की है।
40.	Wind energy	पवन ऊर्जा	NTPC has commissioned its first wind energy based 50 MW project in Gujarat.	एनटीपीसी ने गुजरात में 50 मेगावाट की अपनी प्रथम पवन ऊर्जा आधारित परियोजना चालू की है।
41.	Sustainable development	सतत विकास	Sustainable development is intended to meet the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs.	सतत विकास का उद्देश्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी उत्पादन की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान उत्पादन की जरूरतों को पूरा करना है।

42.	Socio-economic status	सामाजिक-आर्थिक स्थिति	Ministry of Power is making continuous efforts through its PSUs to improve the socio-economic status of project effected persons.	विद्युत मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।
43.	Good corporate citizen	सुनिगमित नागरिक	PSUs should recognize the importance of good corporate citizen .	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुनिगमित नागरिक के महत्व को समझना चाहिए।
44.	Powers conferred	प्रदत्त शक्तियां	In exercise of powers conferred under Section 178 of Electricity Act, 2003 the Central Electricity Regulatory Commission issues regulation from time to time.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग समय-समय पर विनियम जारी करता है।
45.	Quick and easy access	शीघ्र एवं सुगम पहुंच	E-Court System - Saudamini offers quick and easy access to CERCs legal system.	ई-कोर्ट प्रणाली - सौदामिनी सीईआरसी की विधिक प्रणाली के लिए शीघ्र एवं सुगम पहुंच उपलब्ध कराती है।
46.	Disbursement	संवितरण	During the financial 2017-18, REC has made disbursement of Rs. 246.79 Crore to North Eastern Projects.	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरईसी ने पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए 246.79 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।
47.	Barring a few	कुछ को छोड़कर	Most of the states, barring a few , have placed award for execution of projects and works are in progress.	कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने परियोजनाओं के निष्पादन का ठेका दे दिया है और कार्य प्रगति पर है।
48.	Job Oriented Skill Development Training Programme	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	PSUs are supporting job oriented skill development programmes for youths from weaker section of the society.	पीएसयू समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सहायता कर रहे हैं।

49.	Two pronged approach	दो पक्षीय दृष्टिकोण	Government of India has adopted two pronged approach to cater to the energy demand.	ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दो पक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है।
50.	Innovative policy measure	अभिनव नीतिगत उपाय	Efforts are also being made to use energy efficiently in the demand side through innovative policy measures .	अभिनव नीतिगत उपायों के जरिए मांग पक्ष में ऊर्जा का दक्षतापूर्ण उपयोग करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
51.	Selection criteria	चयन मानदंड	Ministry of Power has notified transparent selection criteria for awarding sites to private developers.	विद्युत मंत्रालय ने निजी विकासकर्ताओं को स्थल ठेके पर देने के लिए पारदर्शी चयन मानदंड अधिसूचित किए हैं।
52.	Regulation	विनियम	At present no regulation is under consideration in the Ministry of Power.	वर्तमान में कोई विनियम विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।
53.	Funding	वित्तपोषण	The Government of India is not funding any Thermal Power Project in Uttar Pradesh.	भारत सरकार उत्तर प्रदेश में किसी ताप विद्युत परियोजना का वित्तपोषण नहीं कर रही है।
54.	Strategies	युक्तियां	Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG) suggested some strategies for increase the gas availability	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ युक्तियां सुझाई हैं।
55.	Procurement	प्रापण	Central Government has advised the states to tie up for procurement of power in accordance with their anticipated demand supply scenario.	केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके प्रत्याशित मांग-आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार विद्युत के प्रापण की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

56.	Environment clearance	पर्यावरण स्वीकृति	The status of environment clearance is being monitored regularly by Central Electricity Authority (CEA) and Ministry of Power.	पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
57.	Full cooperation	पूरा सहयोग	The Union Government is committed to extending full cooperation to the State Government for ensuring 24x7 power supply to the consumers in the State.	राज्य में उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
58.	Conventional source	परम्परागत स्रोत	India's capacity addition target during 12th Five Year Plan (2012-17) was 88,537 MW from conventional sources	12वीं पंचवर्षीय योजना(2012-17) के दौरान परम्परागत स्रोतों से भारत का क्षमता संवर्धन लक्ष्य 88,537 मेगावाट था।
59.	Comprehensive reforms	व्यापक सुधार	The enactment of Electricity Act, 2003 along with the policies and regulations made thereunder have brought in comprehensive reforms in the electricity sector with the overall objective of extending benefits to the end consumers and balanced growth of the sector.	विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन और उसके तहत बनाई गई नीतियों और विनियमों ने अन्तिम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और इस क्षेत्र के संतुलित विकास के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं।
60.	Re-organise	पुनःसंगठित करना	All States have now re-organized their State Electricity Boards.	सभी राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों को पुनःसंगठित कर दिया है।
61.	Amendment	संशोधन	No amendments have been made to the National Electricity Policy till date.	राष्ट्रीय विद्युत नीति में अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

62.	Working Group	कार्यदल	This Ministry has received recommendations of the Working Group on power sector.	विद्युत क्षेत्र संबंधी कार्यदल की सिफारिशें इस मंत्रालय को प्राप्त हो गई हैं।
63.	Reasonable and competitive rate	उचित और प्रतिस्पर्धी दर	It is the responsibility of State Government to ensure availability of electricity to consumers at reasonable and competitive rates .	उपभोक्ताओं को उचित और प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।
64.	Borne	वहन करना	The entire cost of the project will be borne by the Government of India through the Plan Scheme of Ministry of Power	परियोजना की संपूर्ण लागत विद्युत मंत्रालय की योजनागत योजना के जरिए सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
65.	Fair and competitive market	उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार	The Power exchange is a Market Infrastructure Institution that provides a fair and competitive market for trading in electricity	पावर एक्सचेंज एक बाजार अवसंरचनात्मक संस्थान है जो विद्युत में व्यापार के लिए एक उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराता है।
66.	Determine	निर्धारित करना	State Governments may grant subsidy to any consumer or class of consumers in the tariff determined by the SERCs	राज्य सरकारें किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को एसईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क में सब्सिडी दे सकती हैं।
67.	Procure	प्रापण	At present power is procured by Distribution Licenses based on Merit Order despatch.	वर्तमान में विद्युत का प्रापण मैरिट आर्डर डिस्पैच के आधार पर वितरण लाइसेंसियों द्वारा किया जाता है।
68.	Erection	लगाना	Power plant equipment erection is under progress.	विद्युत संयंत्र उपकरण लगाने का काम चल रहा है।
69.	Envisage	परिकल्पना करना	The plan envisages implementation of the scheme with cooperation and consent of promoters	इस योजना में प्रवर्तकों के सहयोग और सहमति से योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

70.	Inhabited	बसावट वाले	All the inhabited census villages across the country stand electrified on 28.04.2018.	संपूर्ण देश में बसावट वाले सभी जनगणना गांवों का 28-04-2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है।
71.	Commercial principle	वाणिज्यिक सिद्धांत	Developer can establish generating station based on their commercial principles .	विकासकर्ता अपने वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उत्पादन केंद्र स्थापित कर सकता है।
72.	Pre-construction activities	निर्माण-पूर्व गतिविधियां	Government has given approval for incurring Rs.1600 crore for pre-construction activities for Dibang Multipurpose project of 2880 MW.	सरकार ने 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए 1600 करोड़ रुपए का व्यय करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।
73.	Sufficient power	पर्याप्त विद्युत	Sufficient power has been made available to the States in NE Region to meet their demand	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों को उनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराई गई है।
74.	Address the issue	मुद्दे का समाधान करना	At present, there is no proposal under consideration to set up a Power Sector Council to address the issue between the Centre and the States related to electricity sector.	केंद्र और राज्यों के बीच विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए विद्युत क्षेत्र परिषद स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
75.	Share	हिस्सा	By the end of 2026-27, share of generation from coal based power plants is likely to reduce to about 58%.	कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादन का हिस्सा 2026-27 के अंत तक लगभग 58 प्रतिशत कम होने की संभावना है।
76.	Dynamic sector	गतिशील क्षेत्र	Electricity sector is a dynamic sector and reform initiatives are taken by the Government as and when need arises.	विद्युत क्षेत्र एक गतिशील क्षेत्र है और जब भी आवश्यकता होती है, सरकार द्वारा सुधार पहले की जाती है।

77.	Best practices	उत्कृष्ट प्रक्रियाएं	The transmission lines are planned as per the requirement in the electricity grid by adopting the best practices available in the world.	विद्युत ग्रिड में आवश्यकता के अनुसार पारेषण लाइनों की योजना विश्व में उपलब्ध उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को अपनाकर बनाई जाती है।
78.	Upfront allocation	अग्रिम आबंटन	There is no upfront allocation of funds for any State under DDUGJY and Saubhagya.	डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अन्तर्गत किसी राज्य को कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है।
79.	Retail supply tariff	खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क	The responsibility of determination of retail supply tariff in Delhi lies with Delhi Electricity Regulatory Commission.	दिल्ली में खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क के निर्धारण का उत्तरदायित्व दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का है।
80.	Finalizing	अन्तिम निर्णय लेना	The comments/ suggestions received from Stakeholders are carefully considered by Commission while finalizing the tariff order.	प्रशुल्क आदेश का अन्तिम निर्णय लेते समय पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।
81.	Awareness	जागरूकता	Systematic efforts have been made to create awareness on energy conservation in the country.	देश में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं।
82.	Governed	शासित	The expenditure of CSR funds spend by Power CPSEs are governed/ guided by Section 135(5) of the Companies Act 2013 of Govt. of India.	विद्युत सीपीएसई द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधि का व्यय भारत सरकार के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) द्वारा शासित/निर्देशित होता है।
83.	In return	के बदले में	There are no specific programme/scheme of the Government of India for providing benefits to citizens in return for conservation.	संरक्षण के बदले में लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का कोई विशिष्ट कार्यक्रम/योजना नहीं है।

84.	Host state	मेजबान राज्य	12% free power given to the host state to ensure the support of State Government in execution of the project.	परियोजना के निष्पादन में राज्य सरकार की सहायता सुनिश्चित करने के लिए मेजबान राज्य को 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत दी जाती है।
85.	Time bound	समयबद्ध	Time bound appraisal norms have been evolved for examination of DPRs in Central Electricity Authority (CEA).	डीपीआर की जांच करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में समयबद्ध मूल्यांकन मानदंड तैयार किए गए हैं।
86.	De-licensed activity	लाइसेंस-मुक्त गतिविधि	Generation of electricity is a de-licensed activity .	विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है।
87.	Forecasting system	पूर्वानुमान प्रणाली	Forecasting system shall facilitate System Operators in better management of grid operation.	पूर्वानुमान प्रणाली ग्रिड प्रचालन के बेहतर प्रबंधन में प्रणाली प्रचालकों को सुविधा प्रदान करेगी।
88.	Manufacturing	विनिर्माण	Department of Industrial Policy & Promotion has issued Public Procurement (Preference to Make in India), Orders, 2017 to encourage "Make in India" and to promote manufacturing and production of goods and services in India.	भारत में "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने एवं वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश, 2017 जारी किया है।
89.	Formulate	बनाना	An R&D Mission shall be formulated to encourage development of new technology in renewable energy sector.	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक आरएंडडी मिशन बनाया जाएगा ।
90.	Key parameter	प्रमुख प्राचल	State-wise targets and achievements for key parameters of UDAY in respect of AT&C losses and ACS-ARR gap have been fixed by the Government.	सरकार द्वारा एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अन्तर के संबंध में उदय के प्रमुख प्राचलों के लिए राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां निर्धारित की गई हैं।

91.	Bifurcation	विभाजन	A committee was constituted after the bifurcation of Andhra Pradesh into two states namely Andhra Pradesh and Telangana for resolving issues related to Power Sector.	आंध्र प्रदेश के दो राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजन के पश्चात विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।
92.	Dissolve	भंग करना	Committee has been dissolved vide OM dated 3 rd January, 2018.	दिनांक 3 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत समिति भंग कर दी गई ।
93.	Operational	प्रचालनात्मक	The state of Gujarat has joined UDAY only for operational turnaround of its DISCOMs.	गुजरात राज्य अपने डिस्कामों के केवल प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उदय में शामिल हुआ है।
94.	Inherent	अन्तर्निहित	Transmission and Distribution (T&D) losses, to some extent, are inherent part of the system.	पारेषण और वितरण हानियां कुछ सीमा तक प्रणाली का अन्तर्निहित भाग हैं।
95.	Proactively	अग्रिम कार्रवाई करना	The Government of India is pursuing proactively for early resolution of issues with stakeholders.	भारत सरकार पणधारकों के साथ मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
96.	Terminate	समाप्त करना	State Govt. terminated the agreement with developer for execution of project.	राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए विकासकर्ता के साथ करार समाप्त कर दिया है।
97.	Stalled	अवरूद्ध	Due to Financial crunch with the contractor/ developer, works are stalled since July, 2017.	ठेकेदार/विकासकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य जुलाई, 2017 से अवरूद्ध हैं।
98.	Anticipated cost	प्रत्याशित लागत	Latest cost/ anticipated cost of the project is as per data submitted by the project authorities to CEA.	परियोजना की नवीनतम लागत/ प्रत्याशित लागत परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सीईए को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार हैं।

99.	Demonstration projects	प्रमाणीकरण परियोजना	Demonstration projects have been successfully completed in some States/UTs.	कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रमाणीकरण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं।
100.	Gist of the findings	जांच परिणामों का सार	The gist of the findings of the case studies on the implementation of LED street lights projects in Himachal Pradesh and Rajasthan is under review by the Government.	हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एलईडी स्ट्रील लाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मामला अध्ययनों के जांच परिणामों के सार की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।